LD ****

भविष्य का बजटः युवाओं की उम्मीदें बंधी

भारत का सर्वाधिक प्रसारित हिन्दी दैनिक

"कलम, बलिदान और स्वाभिमान की परिभाषा"

PunjabKesari.com PunjabKesari.com @punjabkesaricom

पूंजी व्यय 35 प्रतिशत बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़

संस्थापकः शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

पंजाब केसरी BUDGET 2022

Punjab Kesari, Delhi
वर्ष : 39 / अंक : 33
मूल्य ₹ 4.50 16 नेपाली रुपए/हवाई जहाज से ₹ 10.00
पृष्ठ संख्या 16, Ph.: 011-30712200, 45212200
दिल्ली, जालन्धर, अम्बाला, जयपुर और अजमेर से एक साथ प्रकाशित

बुधवार 2 फरवरी 2022
◆ दिल्ली ◆तदनुसार 20 माघ 2078

युवा भारत युवा अखबार!

बजटः इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि हम आजाद का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं जो अगले 25 वर्षों की लंबी यात्रा के बाद इंडिया@100 पर पहुंचाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए इंडिया@75 से इंडिया@100 की ओर ले जाने की बुनियाद रखना है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा विजन अगले 25 वर्षों में सूक्ष्म आर्थिक स्तर-समग्र कल्याण पर बल देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में मदद करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, टेक्नोलॉजी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की मदद से निजी निवेश प्रारंभ करने के प्रभावी चक्र से लोगों को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध कराना है। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इंफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट कोविड-19 के प्रभावों से उबरने और स्थिरीकरण के लिए है। बजट में स्टार्ट-अप्स के लिए एमएसएमई और इंडिया इंक के लिए कुछ पहल की गई है। ईसीएलजेएस योजना का विस्तार एमएसएमई के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। कर छूट की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, जो मेरी राय में एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। नई निगमित विनिर्माण इकाइयों के लिए 15 फीसदी की कर दर तय की गई है, जो विनिर्माण गतिविधियों को और बढ़ावा देगी।

दरियागंज में दुकान पर बजट भाषण को सुनते लोग। — फोटोः मिहिर सिंह

क्रेडाई नेशनल नार्थ के वाइस प्रेसिडेंट व गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 एक संतुलित बजट है जो देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था, न कि केवल विशेष क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना। हमारा मानना है कि जब सभी उद्योग सुधार और विकास के पथ पर बने रहते हैं तो जीविका को मजबूत आधार मिलता है और सभी उद्योगों को समान रूप से बढ़ावा मिलता है। आज के बजट में सभी के लिए किफायती आवास और आवास पर बहुत जोर दिखाई दिया। फिनमैप के को-फाउंडर और सीईओ कुमार बिनीत ने बजट बजट विकास के बारे में था और यह केवल कैपेक्स व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ हो सकता है, जिसे वित्त मंत्री ने लगभग 35% बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से केपेक्स व्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मैक्रो के साथ-साथ सूक्ष्म विकास भी होगा। एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन रियल एस्टेट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन तथा प्रसिडेंट सिग्नेचर ग्लोबल, फाउंडर एंड चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा सरकार ने हमेशा अफोर्डेबल आवास पर ध्यान केंद्रित किया है और इस बजट में, पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए के आवंटन के संबंध में घोषणा की गई थी, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। यह समग्र आवास उद्योग के लिए एक प्रमुख बूस्टर डोज हो सकता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा ये बहुत ही प्रगतिशील बजट है, ये पिछले साल के बजट की निरंतरता में है। इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस बजट ने शहरीकरण और MSME पर बहुत फोकस किया है, MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है।

क्रेडाई नेशनल नार्थ के वाइस प्रेसिडेंट व गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 एक संतुलित बजट है जो देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित था, न कि केवल विशेष क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना। हमारा मानना है कि जब सभी उद्योग सुधार और विकास के पथ पर बने रहते हैं तो जीविका को मजबूत आधार मिलता है और सभी उद्योगों को समान रूप से बढ़ावा मिलता है। आज के बजट में सभी के लिए किफायती आवास और आवास पर बहुत जोर दिखाई दिया। फिनमैप के को-फाउंडर और सीईओ कुमार बिनीत ने बजट बजट विकास के बारे में था और यह केवल कैपेक्स व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ हो सकता है, जिसे वित्त मंत्री ने लगभग 35% बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से केपेक्स व्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के मैक्रो के साथ-साथ सूक्ष्म विकास भी होगा।